**भारत सरकार**
**संचार मंत्रालय**
**दूरसंचार विभाग**

**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न सं. 2848**
**उत्तर देने की तारीख 06 अगस्त, 2025**

**लद्दाख के दूरदराज के क्षेत्रों में मोबाइल/इंटरनेट सेवाओं की गुणवत्ता**

**2848. श्री मोहम्मद हनीफ़ाः**
क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि डिजिटल अवसंरचना में हाल ही में हुए सुधारों के बावजूद, नेटवर्क कंजेशन 144 आरसीसी एनपीडी रोड नेयराक्स गांव जैसे लद्दाख के दूरदराज के क्षेत्रों में मोबाइल और इंटरनेट सेवाओं की गुणवत्ता को बुरी तरह प्रभावित कर रही है क्योंकि ये क्षेत्र श्रमिक बस्तियों, जीआरईएफ के शिविरों और निम्मू-पदम-दारचा (एनपीडी) सड़क पर भारी यातायात के कारण अत्यधिक आबादी वाले हो गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा लद्दाख के ग्रामीण और सीमावर्ती गांवों में उन्नत, उच्च-बैंडविड्थं वाला और निर्बाध मोबाइल नेटवर्क कवरेज सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने हैं, जो डिजिटल कनेक्टिविटी पर निर्भर पर्यटकों, छात्रों और आवश्यक सेवाओं के बढ़ते दबाव को कम कर सके; और

(ग) क्या सरकार का सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) या डिजिटल इंडिया पहल के अंतर्गत लद्दाख जैसे पहाड़ी, जनजातीय और सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए कोई विशेष दूरसंचार विकास पैकेज या योजना आरंभ करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**
**संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री**
**(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)**

(क) मोबाइल सेवाओं के लिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित जून-2025 की कार्य-निष्पादन निगरानी रिपोर्ट के अनुसार सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं ने लद्दाख

क्षेत्र सहित जम्मू और कश्मीर लाइसेंस सेवा क्षेत्र में सेवा की गुणवत्ता के निर्धारित बैंचमार्क को प्राप्त कर लिया है।

(ख) और (ग) लद्दाख सहित देश के दूरदराज, पहाड़ी, जनजातीय, सीमावर्ती और ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च बैंडविड्थ क्षमता वाली इंटरनेट/ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी और मोबाइल सेवाएं प्रदान करने के लिए डिजिटल भारत निधि (डीबीएन) [पूर्ववर्ती सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ)] के तहत निम्नलिखित परियोजनाएं शुरू की गई हैं:

i. **भारतनेट परियोजना** - भारतनेट परियोजना का उद्देश्य देश की सभी ग्राम पंचायतों और गांवों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करना है। लद्दाख की सभी 193 ग्राम पंचायतों (जीपी) को सेटेलाइट के माध्यम से सेवा प्रदान करने के लिए तैयार कर दिया गया है।
ii. **संशोधित भारतनेट कार्यक्रम (एबीपी) -** इस कार्यक्रम के अंतर्गत, देश में भारतनेट चरण-I और चरण-II के मौजूदा नेटवर्क को उन्नत किया जाएगा और शेष 42,000 ग्राम पंचायतों में नेटवर्क का क्रिएशन किया जाएगा। देश के शेष बिना ग्राम पंचायतों वाले गाँवों (लगभग 3.8 लाख) को उनकी संबंधित ग्राम पंचायतों से प्राप्त माँग के आधार पर कनेक्टिविटी प्रदान करने का प्रस्ताव है।
iii. **4जी सेचुरेशन और अन्य मोबाइल परियोजनाएं** - लद्दाख के सेवा से वंचित दूरदराज और ग्रामीण क्षेत्रों में 175 मोबाइल टावर चालू किए गए हैं।

*****